C O N T E N T S

Sixteenth Series, Vol. XX, Tenth Session, 2016/1938 (Saka)
No. 10, Tuesday, November 29, 2016/Agrahayana 08, 1938 (Saka)

SUBJECT	PAGES
MEMBER SWORN	9
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
*Starred Question Nos. 181 and 182	10-27
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
Starred Question Nos. 183 to 200	28-107
Unstarred Question Nos. 2071 to 2300	108-668

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

PAPERS LAID ON THE TABLE 670-676

MATTERS UNDER RULE 377 678-705

(i) Need to complete the construction of Lower Subansiri Hydro Electrical Project in Assam

Shri Ram Prasad Sarmah 679

(ii) Need to fast track the recovery of big loans and waiving off small loans of farmers in Uttar Pradesh particularly in Hamirpur Parliamentary Constituency

Kunwar Pushpendra Singh Chandel 680

(iii) Need to construct under pass and road over bridges on Udhna-Jalgaon railway line in Bardoli Parliamentary Constituency, Gujarat

Shri Prabhubhai Nagarbhai Vasava 681

(iv) Need to include Mahra/Mahara caste of Chhattisgarh in the list of Scheduled Castes

Shri Vikram Usendi 682

(v) Need to set up a super speciality Hospital/Polyclinic and six more CGHS Wellness Centres in Jabalpur, Madhya Pradesh

Shri Rakesh Singh 683

(vi) Need to construct an irrigation canal to channelise the water of Chandan dam to Godda, Jharkhand

Shri Nishikant Dubey 684

(vii) Need to ban TV serials depicting wrong portrayal of historical and mythological texts

Shri Sudheer Gupta 685

(viii) Need to take immediate remedial steps to check soil erosion by rivers in various districts of Jharkhand particularly in Palamu and Garhwa districts

Shri Vishnu Dayal Ram 686

(ix) Need to regularise the services of temporary labourers engaged by FCI Depot Ghevra, Delhi

Shri Janardan Singh Sigriwal 687

(x) Need to construct a Road Over Bridge between Hazaribagh Road railway station and Keshwari railway station in Kodarma Parliamentary Constituency, Jharkhand

Shri Ravindra Kumar Ray 688

(xi) Need to bring a policy to monitor the working of labour contractors

Shrimati Rakshatai Khadse 689

(xii) Need to develop public infrastructure conducive to differently-abled people in the country

Dr. Virendra Kumar 690

(xiii) Need to start work on the North-South Corridor of Diamond Quadrilateral Railway Project to establish high speed railway network in the country

Shri Prahlad Singh Patel 691

(xiv) Need to declare and develop the Sindkhed Raja, the birth place of Rajmata Jijau - mother of Chhatrapati Shivaji - in Buldhana district, Maharashtra as a historical place of international importance

Shri Rajeev Satav 692

(xv) Need to provide financial assistance to Karnataka affected by drought

Shri S.P. Muddahanume Gowda 693

(xvi) Need to provide financial support to Solar Pump programme in North Eastern States

Shri Gaurav Gogoi 694

(xvii) Need to develop tourism infrastructure in Sirumalai Hills near Dindigul in Tamil Nadu

Shri M. Udhayakumar 695

(xviii) Need to construct a service Road on National Highway No. 45 at Samayapuram village in Perambulur Parliamentary Constituency of Tamil Nadu

Shri R. P. Marutharajaa 696

(xix) Need to bring normalcy along the Line of Control

Prof. Saugata Roy 697

(xx) Need to provide remunerative price of paddy and jute to farmers in West Bengal particularly in Krishnanagar Parliamentary Constituency

Shri Tapas Paul 698

(xxi) Need to declare Malkangiri district in Odisha as a Japanese Encephalitis Vaccine District and start timely vaccination in the district

Shri Balabhadra Majhi 699

(xxii) Need to implement the Coastal Regulation Zone (CRZ) Notification, 2011

Shri Gajanan Kirtikar 700

(xxiii) Need to provide financial assistance to cooperative sugar factories in Andhra Pradesh

Shri Muthamsetti Srinivasa Rao(Avanthi) 701

(xxiv) Need to hand over the land occupied by Assam Rifles Complex to the State Government of Tripura for setting up of a multi-discipline Sports and Cultural Complex

Shri Jitendra Chaudhury 702

(xxv) Need to establish a 50 bed AYUSH Hospital in Hisar, Haryana under National AYUSH Mission

Shri Dushyant Chautala 703

(xxvi) Regarding relaxation in restrictions imposed by Archaeological Survey of India for undertaking new construction/repair of houses in Thrissur district of Kerala

Shri C.N. Jayadevan 704

TAXATION LAWS (SECOND AMENDMENT) BILL, 2016 706-726

Motion to consider 721-724

Shri Arun Jaitley 721-722

Clauses 2 to 5 and 1 724-726

Motion to pass 726

ANNEXURE – I

Member-wise Index to Starred Questions 727

Member-wise Index to Unstarred Questions 728-733

ANNEXURE – II

Ministry-wise Index to Starred Questions 734

Ministry-wise Index to Unstarred Questions 735

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shrimati Sumitra Mahajan

THE DEPUTY SPEAKER

Dr. M. Thambidurai

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shri Arjun Charan Sethi

Shri Hukmdeo Narayan Yadav

Shri Anandrao Adsul

Shri Pralhad Joshi

Dr. Ratna De (Nag)

Shri Ramen Deka

Shri Konakalla Narayana Rao

Shri Hukum Singh

Shri K.H. Muniyappa

Dr. P. Venugopal

SECRETARY GENERAL

Shri Anoop Mishra

LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

Tuesday, November 29, 2016/Agrahayana 08, 1938 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[HON. SPEAKER *in the Chair*]

… (*Interruptions*)

MEMBER SWORN

HON. SPEAKER: Secretary General will now call the name of the Member who has not taken oath or affirmation.

SECRETARY GENERAL : Shri Pradan Baruah. Assam

Shri Pradan Baruah (Lakhimpur) - Oath - Assamese

… (*Interruptions*)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं इनकम टैक्स एक्ट अमेंडमेंट के बारे में कुछ कहना चाहता हूं।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अभी नहीं, 12 बजे देखेंगे।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न 181

श्री रामदास सी. तडस

...(व्यवधान)

11.03 hours

(At this stage Shri Kalyan Banerjee and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.)

...(व्यवधान)

11.04 hours

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

HON. SPEAKER:Shri Ramdas C. Tadas.

(Q. 181)

श्री रामदास सी. तडस: माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र वर्धा में बोर जो कि बहुत ही घना एवं पुराना जंगल है, को वर्ष 2014 में 47वां राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व क्षेत्र घोषित किया।...(व्यवधान)

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वर्ष 2014 से अब तक बोर राष्ट्रीय रिजर्व क्षेत्र के विकास एवं रखरखाव हेतु क्या कदम उठाए गए हैं? जंगल के बाहर आम नागरिकों एवं पशुओं की सुरक्षा की क्या व्यवस्था की गई है?...(व्यवधान)

11.04 ½ hours

(At this stage Shri Kanti Lal Bhuria and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.)

श्री अनिल माधव दवे: माननीय अध्यक्ष जी, वर्ष 2016-17 में केंद्र सरकार ने 380 करोड़ रुपए टाइगर प्रोजेक्ट पर खर्च किए हैं। इसका 40 प्रतिशत हिस्सा राज्य सरकारों ने भी खर्च किया है। ...(व्यवधान) हम इस बात की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जंगल के बाहर मैन एनीमल और एनीमल टू एनीमल कन्फलिक्ट्स कम से कम हों। इस बारे में लोगों को जागृत करने की जरूरत है, यह समझाने की जरूरत है कि जिसके कारण यह कन्फलिक्ट होता है, वह न हो।

अध्यक्ष महोदया, दूसरी बात यह है कि जानवर जिस कारण से जंगल से बाहर आता है ...(व्यवधान) वह जंगल से बाहर न आये और जंगल की परिधि में रहे, उसके लिए भी अलग-अलग प्रयत्न किये जा रहे हैं। ...(व्यवधान)

श्री रामदास सी. तडस: अध्यक्ष महोदया, महाराष्ट्र में कुल कितने टाइगर रिजर्व क्षेत्र हैं तथा चन्द्रपुर के तदोबा एवं वर्धा के बोर टाइगर रिजर्व क्षेत्र में कितने बाघ हैं? ...(व्यवधान) इन दोनों बाघ रिजर्व क्षेत्रों में बाघों की संख्या बढ़ाने के साथ-साथ देश भर में टाइगर रिजर्व क्षेत्र में बाघों की संख्या बढ़ाने के लिए क्या व्यवस्था की गयी है? ...(व्यवधान) इसके साथ-साथ मध्य प्रदेश के कान्हा नेशनल पार्क एवं केरल की परियार टाइगर रिजर्व में पर्यटकों के लिए सुविधा बढ़ाने पर क्या विचार किया गया है? ...(व्यवधान)

श्री अनिल माधव दवे : अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य ने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के साथ-साथ देश के बाकी हिस्सों में स्थित टाइगर रिजर्व क्षेत्र के बारे में प्रश्न पूछा है। ...(व्यवधान) हमारे प्रयत्नों के कारण आज विश्व के 70 प्रतिशत बाघ भारत में हैं। ...(व्यवधान) अगर विश्व में 100 बाघ हैं, तो 70 बाघ भारत के पास हैं। ...(व्यवधान) हमारे पास कुल 2200 के आसपास बाघ हैं। ...(व्यवधान) उन बाघों का संरक्षण बहुत अच्छे ढंग से हो रहा है, जिसके कारण उनकी संख्या में निरंतर विस्तार हो रहा है। ...(व्यवधान) हमारे पास करीब-करीब 1668 बाघों के फोटोग्राफ्स हैं, जिन्हें हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ...(व्यवधान) हम इसके माध्यम से यह पता लगा सकते हैं कि निश्चित बाघ किस क्षेत्र में है और वह जिंदा है या नहीं। ...(व्यवधान) महाराष्ट्र में बाघों के संरक्षण के लेकर महाराष्ट्र सरकार पर्याप्त परियोजना, प्रयास कर रही है। ...(व्यवधान) केन्द्र सरकार भी उसमें सहयोग कर रही है। ...(व्यवधान)

श्री विनायक भाऊराव राऊत: अध्यक्ष महोदया, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में टाइगर प्रोजैक्ट के लिए ज्यादा से ज्यादा निधि का प्रावधान किया गया है ...(व्यवधान) लेकिन दुर्भाग्य से महाराष्ट्र के तदोबा जंगल में कई महीने पहले जय नाम का बाघ, जो देश का अभिमान था, वह लापता हो गया। ...(व्यवधान) उसे ढूंढ़ने के लिए कई प्रयास किये गये। ...(व्यवधान) अगर इस तरह से बाघ लापता होंगे, तो यह एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया, मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा निधि देने के बाद भी महाराष्ट्र सरकार के जिस अधिकारी ने जय बाघ पर ध्यान नहीं दिया, उस बारे में आप क्या कर रहे हैं? ...(व्यवधान) भविष्य में ऐसी घटना दोबारा न हो, इसके लिए आपने स्टेट गवर्नमैंट को क्या आदेश दिये हैं? ...(व्यवधान)

श्री अनिल माधव दवे : अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य ने जय नाम के बाघ के बारे में प्रश्न पूछा है। ...(व्यवधान) यह सही है कि जय नाम का टाइगर पिछले छः महीने से नहीं मिल रहा है। ...(व्यवधान)

अध्यक्षा जी, मैं बताना चाहता हूं कि एक टाइगर का क्षेत्र सौ वर्ग किलोमीटर का होता है और वह उसके अंदर किसी दूसरे को नहीं आने देता। ...(व्यवधान) इतने बड़े क्षेत्र में, जो कि घना जंगल भी है, हम उसे ढूंढ़ने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। ...(व्यवधान) हमने उसे अभी डेड डिक्लेयर नहीं किया है। ...(व्यवधान) वह जीवित हो सकता है। ...(व्यवधान) वर्षा के मौसम में उसे जंगल में ढूंढ़ने में कठिनाई हो रही थी। ...(व्यवधान) चूंकि अब वर्षा का मौसम खत्म हो गया है, इसलिए हम उसे अभी भी ढूंढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ...(व्यवधान) महाराष्ट्र सरकार अपने राज्य के बाघों के संरक्षण के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है। ...(व्यवधान) कर्नाटक भी इसमें प्रयत्न कर रहा है। मध्य प्रदेश भी अपनी जगह बहुत अच्छा प्रयत्न कर रहा है। ...(व्यवधान) ये सब प्रयत्न जारी हैं, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूं कि अगर दो-ढाई हजार

बाघ हैं, तो उसमें एक निश्चित प्रमाण में बाघों की मृत्यु जन्म के साथ एक रेशियो में बनी हुई है। ...(व्यवधान) उम्र के कारण, एक-दूसरे से संघर्ष के कारण या कोई और बीमारी के कारण उनकी मृत्यु होती है। ...(व्यवधान) ये सब कारण हैं, लेकिन बाघ संरक्षण क्या होता है, यह विश्व के लोग भारत के माध्यम से सीखते हैं। ...(व्यवधान) यानी विश्व में भारत एक प्रमाण है कि टाइगर के प्रोटेक्शन और रिजर्व कंजर्वेशन के लिए क्या करना चाहिए? ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अभी शायद मध्य प्रदेश में आपसी संघर्ष में एक बाघ चला गया था।

...(व्यवधान)

DR. KULMANI SAMAL: Respected hon. Speaker, Satkosia and Similpal are the two tiger reserves in Odisha. In 2014-15 and 2015-16, the allocation of funds for these two reserves has come down and the monitoring system is also not maintained well. … (*Interruptions*)

So, I would like to ask the hon. Minister, through you, as to when he is going to allocate sufficient funds and also when he is going to maintain the monitoring system well. … (*Interruptions*) Thank you.

श्री अनिल माधव दवे: मैडम, यह प्रश्न महाराष्ट्र से सन्दर्भित है, फिर भी मैं बताना चाहता हूं कि जवाब के साथ एक स्टेटमेंट दिया गया है। ...(व्यवधान) ओडिशा के बारे में अगर माननीय सदस्य कोई स्पेसिफिक प्रश्न पूछेंगे तो मैं उसका जवाब उनको लिखित रूप में बाद में दे दूंगा।...(व्यवधान)

श्री नाना पटोले: अध्यक्ष महोदया, माननीय मंत्री जी ने एशिया के सबसे बड़े टाइगर - जय के बारे में यहां मालूमात दी है। ...(व्यवधान) मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि जो बड़े टाइगर होते हैं, उनको मारकर चाइना जैसे देशों में स्मगलिंग की जाती है।...(व्यवधान) माननीय मंत्री जी ने कहा था कि अगर समय आया तो हम इसमें इंटरपोल की मदद भी लेंगे।...(व्यवधान) ऐसा उन्होंने नागपुर में कहा था।...(व्यवधान) मेरा दावा है कि टाइगर जय, जो एशिया का सबसे बड़ा टाइगर था, उसको मारा गया है।...(व्यवधान) उसकी पोचिंग की गयी है और चाइना जैसे देश में उसकी स्मगलिंग की गयी है।...(व्यवधान) क्या यह बात सही है?...(व्यवधान)

श्री अनिल माधव दवे: मैडम, टाइगर जय के संबंध में, मैं इतना ही कह सकता हूं कि अभी तक उसके मर जाने का कोई प्रमाण नहीं मिला है। ...(व्यवधान) उसे ढूंढ़ने के प्रयास जारी हैं, लेकिन यह बात सही है कि साउथ ईस्ट एशिया और चाइना में बाघों के अंगों को लेकर बाजार में पर्याप्त मांग होती है।...(व्यवधान) हम उस मांग के आधार पर इन चीजों पर नजर रखते हैं और पड़ोसी देशों से बात करते हैं।...(व्यवधान)

आवश्यकता पड़ने पर इंटरपोल की भी मदद लेते हैं और हम इस बात की पूरी कोशिश करते हैं कि बाघ के किसी अंग का व्यापार भारत के बाहर न हो पाए, लेकिन हमारी सीमाएं हैं। ...(व्यवधान) इंटरपोल इस काम में हमारी पूरी मदद करती है। ...(व्यवधान) जय के संबंध में मैं यह कहना चाहता हूं कि अभी हम न मान लें कि वह मर गया है।...(व्यवधान) अभी हम उसे ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और जैसे ही हमें उसमें सफलता मिलेगी, हम बताएंगे।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : यह क्या बात है?

...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: The House stands adjourned to meet again at 11.30 a.m.

11.13 hours

The Lok Sabha then adjourned till Thirty Minutes past Eleven of the Clock.

11.30 hours

The Lok Sabha reassembled at Thirty Minutes past Eleven of the Clock.

(Hon. Speaker *in the Chair*)

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : नहीं नहीं। अभी कुछ नहीं।

…(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा): मैडम, ऐसा नहीं होता। डेमोक्रेसी में चर्चा के साथ ही सब कुछ होना चाहिए। ...(व्यवधान) हम यह कोशिश कर रहे हैं।...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Now, Q. No. 182 – Shri Gajanan Kirtikar

… (*Interruptions*)

11.31 hours

(*At this stage, Shri D.K. Suresh, Shri Sunil Kumar Mondal and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.*)

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS...contd

(Q. 182)

श्री गजानन कीर्तिकर: माननीय अध्यक्ष जी, वर्तमान समय में स्वर्ण तथा चांदी के आभूषणों में हॉलमार्किंग की व्यवस्था है किंतु हमारे देश में हीरे का कारोबार बड़ी तेजी से फलफूल रहा है। ...(व्यवधान) हीरे के जड़ित आभूषणों का काफी मात्रा में आयात एवं निर्यात किया जाता है। मीडिया रिपोर्ट के माध्यम से ऐसा भी ज्ञात हुआ है कि चीन से नकली एवं घटिया गुणवत्ता वाले हीरे का देश में भारी मात्रा में आयात हो रहा है।...(व्यवधान)

अत: मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि सरकार हीरा खरीदने वाले उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण करने हेतु क्या उपाय कर रही है?...(व्यवधान) हीरा उद्योग के लिए भी हॉलमार्किंग जैसी व्यवस्था शुरु करने पर क्या सरकार विचार करेगी?

श्री सी.आर.चौधरी : माननीय अध्यक्ष जी, वास्तव में प्रिशीयस मैटल्स के ऊपर बी.आई.एस. का एक तरह से काम चालू है।...(व्यवधान) सबसे प्रिशीयस मैटल्स का वर्ष 2000 के अंदर गोल्ड के ऊपर यह काम किया गया। ...(व्यवधान) वर्ष 1999 में आर.बी.आई. की रिक्वैस्ट थी और उन्होंने रिक्वैस्ट की थी कि गोल्ड की जो सेल हो रही है, उनमें अशुद्धता कुछ हद तक है और इसके ऊपर वर्ष 2001 में सर्वे कराया गया था।...(व्यवधान) सर्वे के अनुसार 11 प्रतिशत से लेकर 13 प्रतिशत तक अशुद्धता पाई गई।...(व्यवधान) इसी कारण से आर.बी.आई. और बी.आई.एस. ने निर्णय लिया कि गोल्ड के जितने जेवरात हैं, उनके लिए हॉलमार्किंग का सिस्टम किया जाए। ...(व्यवधान) हालांकि मैं आपसे अर्ज करना चाहूंगा कि यह वॉलंट्री प्रोविजन है। कोई भी जौहरी, कोई भी जेवरात बनाने वाले के लिए यह कम्पलसरी नहीं है कि he should take the licence. यह प्रोविजन लागू होने के बाद, आज की तारीख में 17000 से ज्यादा लाइसेंसी हैं और हमारे 409 एसेइंग एंड हॉलमार्किंग सेंटर्स हैं जहां से गोल्ड जेवरात के ऊपर हॉलमार्किंग की जाती है। ...(व्यवधान) जहां तक माननीय सदस्य ने बताया, मैं आपके माध्यम से अर्ज करना चाहूंगा कि अभी तक हीरे के ऊपर हॉलमार्किंग करने का कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है। ...(व्यवधान) यदि कोई ऐसी बात आई है तो इस पर विभाग विचार करेगा। बाकी आज की तारीख में क्योंकि प्रिशीयस मैटल्स में गोल्ड और सिल्वर को लिया है, हीरे वगैरह को सम्मिलित नहीं किया गया है। **श्री गजानन कीर्तिकर:** माननीय अध्यक्ष जी, विश्व स्वर्ण परिषद की रिपोर्ट के अनुसार देश में लगभग 30 प्रतिशत आभूषण ही हॉलमार्क युक्त हैं। ...(व्यवधान) कुछ हॉलमार्किंग केन्द्रों की गुणवत्ता तथा विश्वसनीयता भी एक चिंता का विषय है। ...(व्यवधान) वर्तमान में

भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 के समर्थकारी प्रावधानों के अनुसार सोने और चांदी के आभूषणों की हॉलमार्किंग को अनिवार्य बनाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।...(व्यवधान)

अत: मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि सरकार द्वारा हॉलमार्किंग को अनिवार्य बनाने में क्या कुछ कठिनाइयां हैं और यदि हैं तो उन कठिनाइयों को दूर करने हेतु सरकार क्या कदम उठा रही है?

श्री सी.आर.चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य ने बहुत अच्छी बात उठायी है कि एक्चुअल में गोल्ड में वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने यह बताया है कि भारत में हॉल मार्किंग केवल 30 परसेंट जेवरात पर ही होती है।...(व्यवधान) यह बात वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट में भी आयी है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया है कि भारत में 50 परसेंट जेवरात जो कि हॉल मार्किंग के नहीं हैं, उनमें आज भी 10 से 15 परसेंट तक इम्प्योरिटीज़ पायी जा रही हैं।...(व्यवधान) इसके लिए कदम उठाने की आवश्यकता है। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि मार्च, 2016 में बीआईएस-2016 एक्ट पारित किया गया है, उसके सेक्शन 14 में यह मेंडेटरी किया जा रहा है कि प्रत्येक ज्वैलर्स को हॉल मार्किंग के सिस्टम को आईएनएच के द्वारा करवाना होगा।...(व्यवधान) इस बारे में रूल्स और रेगुलेशन्स बनाए जा रहे हैं, लेकिन अभी इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है, केवल पास किया गया है, अभी इसको लागू करना बाकी है। इसलिए माननीय सदस्य की चिंता के बारे में मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि उनकी चिंता को विभाग पूर्णतया कंसीडर करेगा और इस बारे में एक्ट भी बनाया जा चुका है।...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Please go to your seats.

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: What is all this?

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: What you are doing is not fair.

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: The House stands adjourned to meet again at 12 o'clock.

11.36 hours

The Lok Sabha then adjourned till Twelve of the Clock.

12.00 hours

The Lok Sabha re-assembled at Twelve of the Clock.

(Hon. Speaker *in the Chair*)

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Hon. Members, I have received notices of Adjournment Motion from Shri Mallikarjun Kharge, Shri Jyotiraditya M. Scindia, Shri K.C. Venugopal, Shri Sudip Bandyopadhyay, Shri Jai Prakash Narayan Yadav, Shri Dharmendra Yadav, Shri Rajesh Ranjan, Shrimati P.K. Shreemathi Teacher, Shri P.K. Biju, Dr. A. Sampath, Shri N.K. Premchandran, Shri P. Kumar, Prof. Saugata Roy, Shri Shailesh Kumar, Shri Jitendra Chaudhury, Adv. Joice, George, Shri Mohammad Salim, Shri M.B. Rajesh, Shri P. Karunakaram and Shri Md. Badaruddoz Khan on different issues.

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: The matters though important do not warrant interruption of business of the day. The matters can be raised through other opportunities. I have, therefore, disallowed all the notices of Adjournment Motion.

… (*Interruptions*)

12.02 hours

(*At this stage, Shri Kalyan Banerjee, Shri K.C. Venugopal, Shri Dharmendra Pradhan and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.*)

… (*Interruptions*)

12.03 hours

PAPERS LAID ON THE TABLE

HON. SPEAKER: Now, Papers to be laid on the Table.

… (*Interruptions*)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI S.S. AHLUWALIA): Madam, I beg to lay on the Table:-

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Society of Agricultural Statistics, New Delhi, for the year 2015-2016, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Society of Agricultural Statistics, New Delhi, for the year 2015-2016.

[Placed in Library, See No. LT 5518/16/16]

(2) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Society of Agricultural Economics, Mumbai, for the year 2015-2016, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Society of Economics Statistics, Mumbai, for the year 2015-2016.

[Placed in Library, See No. LT 5519/16/16]

… (*Interruptions*)

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पंचायती राज मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री परषोत्तम रूपाला) : अध्यक्ष महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) कर्नाटक काजू विकास निगम लिमिटेड, मंगलौर के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कर्नाटक काजू विकास निगम लिमिटेड, मंगलौर के वर्ष 2015-2016 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[Placed in Library, See No. LT 5520/16/16]

(2) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ. 3053(अ) जो 23 सितम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो केन्द्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण और प्रशिक्षण संस्थान तथा मुंबई, कल्याण और चेन्नई स्थित इसके प्रादेशिक प्रयोगशालाओं के सहायक निदेशक और उप निदेशक को इस अधिसूचना के जारी किए जाने के 6 माह के अवधि के लिए उर्वरक निरीक्षिक के रूप में घोषित किए जाने के बारे में है ।

(दो) उर्वरक (नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2016 जो 23 सितम्बर, 2016 भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 3054(अ) में प्रकाशित हुआ था।

[Placed in Library, See No. LT 5521/16/16]

(3) (एक) राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य प्रबंध संस्थान, हैदराबाद के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य प्रबंध संस्थान, हैदराबाद के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

(तीन) राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य प्रबंध संस्थान, हैदराबाद के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 5522/16/16]

(4) बहु-राज्यीय कोऑपरेटिव सोसाइटीज अधिनियम, 2002 की धारा 124 की उपधारा (3) के अंतर्गत बहु-राज्यीय कोऑपरेटिव सोसाइटीज (संशोधन) नियम, 2016, जो 17 अगस्त, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 798 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 5523/16/16]

(5) नाशक कीट और नाशक जीव अधिनियम, 1914 की धारा 4(घ) के अंतर्गत पादप संघरोध (भारत में आयात का विनियमन) (7वां संशोधन) आदेश, 2016, जो 5 अगस्त, 2016 के भारत के राजपत्र की अधिसूचना संख्या का.आ. 2614(अ) में प्रकाशित हुआ था।

[Placed in Library, See No. LT 5524/16/16]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI KIREN RIJIJU): Madam, I beg to lay on the Table:-

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Disaster Management, New Delhi, for the year 2014-2015, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute of Disaster Management, New Delhi, for the year 2014-2015.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 5525/16/16]

… (*Interruptions*)

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णपाल गुर्जर): अध्यक्ष महोदया, मैं कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :-

(एक) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम, नई दिल्ली का वर्ष 2015-2016 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 5526/16/16]

… (*Interruptions*)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES (SHRI BABUL SUPRIYO): Madam, I beg to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of Section 394 of the Companies Act, 2013:-

(i) Review by the Government of the working of the Bharat Heavy Electricals Limited, New Delhi, for the year 2015-2016.

(ii) Annual Report of the Bharat Heavy Electricals Limited, New Delhi, for the year 2015-2016, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 5527/16/16]

(2) A copy each of the following papers (Hindi and English versions):-

(i) Memorandum of Understanding (Hindi and English versions) between the Andrew Yule and Company Limited and the Department of Heavy Industry, Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises, for the year 2016-2017.

[Placed in Library, See No. LT 5528/16/16]

(ii) Memorandum of Understanding (Hindi and English versions) between the Bharat Pumps and Compressors Limited and the Department of Heavy Industry, Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises, for the year 2016-2017.

[Placed in Library, See No. LT 5529/16/16]

(iii) Memorandum of Understanding between the Bharat Heavy Electricals Limited the Department of Heavy Industry, Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises, for the year 2016-2017.

[Placed in Library, See No. LT 5530/16/16]

… (*Interruptions*)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS, MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SHIPPING AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI MANSUKH L. MANDAVIYA): Madam, I beg to lay on the Table:-

(1) A copy of Notification No. G.S.R.3371(E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated 3rd November, 2016 order indicating the supplies of urea to be made by domestic manufacturers of urea to States and Union Territories during Rabi, 2016-17 under sub-section (6) of Section 3 of the Essential Commodity Act, 1955.

[Placed in Library, See No. LT 5531/16/16]

(2) A copy of the Chemical Weapons Convention Rules, 2016 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R.834(E) in Gazette of India dated 30th August, 2016 under Section 56 of the Chemical Weapons Convention Act, 2000.

[Placed in Library, See No. LT 5532/16/16]

… (*Interruptions*)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI C.R. CHAUDHARY): Madam, I beg to lay on the Table:-

(1) A copy of the Food Corporation of India (Staff) (First Amendment) Regulations, 2016 (Hindi and English versions) published in Notification No. EP.1(1)/2015 in Gazette of India dated 10th May, 2016 under sub-section (5) of Section 45 of the Food Corporation Act, 1964.

[Placed in Library, See No. LT 5533/16/16]

(2) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Central Warehousing Corporation, New Delhi, for the year 2015-2016, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Central Warehousing Corporation, New Delhi, for the year 2015-2016. … (*Interruptions*)

[Placed in Library, See No. LT 5534/16/16]

HON. SPEAKER: Hon. Members, please go back to your seats.

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: I am requesting you. Please go back to your seats.

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Let me start 'Zero Hour'.

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Shri Premachandran ji, I have got your notice of privilege. It is under my consideration.

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: The House stands adjourned to meet again at 2.00 pm.

12.06 hours

The Lok Sabha then adjourned till Fourteen of the Clock.

14.02 hours

The Lok Sabha re-assembled at Two Minutes past Fourteen of the Clock.

(Shri Hukum Singh *in the Chair*)

… (*Interruptions*)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : सभापति महोदय, एक मिनट इधर तो देखिए।...(व्यवधान)

माननीय सभापति : पहले मैं 377 पढ़ दूँ।

...(व्यवधान)

14.02 ½ hours

MATTERS UNDER RULE 377*

HON. CHAIRPERSON: Hon. Members, the Matters under Rule 377 shall be treated as laid on the Table of the House. Members may personally handover text of the matter at the Table as per the procedure.

… (*Interruptions*)

* Treated as laid on the Table.

(i) Need to complete the construction of Lower Subansiri Hydro Electrical Project in Assam

SHRI RAM PRASAD SARMAH (TEZPUR): As the Union Government is well aware that Lower Subansiri Hydro Electrical Project/Dam construction work has got delayed for years and in view of present power crises in the country it is high time to take further steps to find out alternative sources of energy to meet our demand and for over all development particularly for North Eastern States. This 2000 MW Lower Subansiri Hydroelectric Project, is the biggest Project undertaken in India on river Subansiri. This project would also be important for India's tactical talk on power with China. If we fail to develop our hydro power project, our negotiating capacity with China will be affected. Initial estimated cost of construction was Rs. 4500 crore but the delay has now escalated the cost to the tune of Rs. 18000 crore thereby escalating the cost of production per unit of energy. A comprehensive Environment Impact Assessment (EIA) study for Lower Subansiri was submitted by NHPC for appraisal, covering all the environmental aspects and baseline data with respect to meteorology, geology, seismology, water quality, land use pattern, terrestrial ecology, wildlife, aquatic ecology, fisheries and socio-economic aspects, as well as disaster management plan. Government should also ensure all mitigation measures so that adverse environment impact be minimized and also ensure to supply of 600 MW to Assam.

I demand from Union Government to complete the rest of construction work of Lower Subansiri Hydro Electrical Projects in larger interest of people of Assam and North East.

(ii) Need to fast track the recovery of big loans and waiving off small loans of farmers in Uttar Pradesh particularly in Hamirpur Parliament Constituency.

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल (हमीरपुर) : भारत इस समय विश्व की सबसे उभरती हुई अर्थव्यवस्था है और हमारे द्वारा उच्च विकास दर का लक्ष्य भी रखा गया है। यह विकास तेजी से हो सके इसके लिए निजी क्षेत्र को निवेश हेतु धन उपलब्ध कराना बहुत जरूरी है जिससे नवीन रोजगार का निर्माण हो सकेगा। यह ऋण निजी क्षेत्र द्वारा एक निश्चित समय में वापस करना होता है परन्तु वर्तमान समय में ऋण वसूली अधिकरणों में लगभग 70 हजार मामले लंबित हैं जो कि एक चिंता का विषय है।

ऋण वसूली के त्वरित निपटान आज समय की मांग है यद्यपि इन मामलों के निपटान की वर्तमान समय-सीमा 180 दिन है परन्तु विभिन्न कारणों से यह मामले वर्षों तक चलते रहते हैं और ऋण वसूली में देरी होती है। आज के समय में रिजर्व बैंक को बड़े देनदारों के नाम सार्वजनिक करने चाहिए। जहां रिजर्व बैंक को इन बड़े देनदारों की साख की चिंता है वहीं मेरे संसदीय क्षेत्र हमीरपुर (उ.प्र.) सहित पूरे बुंदेलखण्ड में औसत कृषि ऋण लगभग 30,000 रूपये है और इसकी वसूली के लिए सभी हथकंडे कर्ज देने वाली वित्तीय संस्थाओं द्वारा अपनाई जाती है और किसानों की गरिमा को ठेस पहुंचने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी जाती है जिसके कारण किसान आत्महत्या करने पर भी मजबूर हो जाता है। पिछले दो दशकों में उत्तर प्रदेश में लगभग 20,000 किसानों ने आत्महत्या कर ली है और कुछ बड़े देनदार प्रचलित कानून की त्रुटियों का लाभ उठाकर बिना ऋण वापिस कर देश से बाहर भाग जाते हैं। इस पर कानून का संशोधन करके अंकुश लगाने की जरूरत है। यदि ऋण वसूली के मामलों का त्वरित निपटान नहीं किया जाएगा तो इससे देश में कारोबार के लिए उचित माहौल नहीं बनेगा और निवेश में कमी आएगी और विकास दर भी प्रभावित होगी तथा मेरे संसदीय क्षेत्र हमीरपुर (उ.प्र.) सहित सम्पूर्ण बुंदेलखण्ड से पिछले 10 वर्षों के दौरान रोजगार के लिए जो 40 प्रतिशत पलायन हुआ है उन लोगों के प्रवास में रोजगार में कमी आएगी और उनकी स्थिति और भी दयनीय हो जाएगी।

अतः मेरा सरकार से यह निवेदन है कि ऋण वसूली के मामलों के त्वरित निपटान के साथ बुंदेलखण्ड के गरीब किसानों के ऋण पर ब्याज को माफ किया जाये।

(iii) Need to construct underpass and road over bridges on Udhna-Jalgaon railway line in Bardoli parliamentary constituency, Gujarat.

श्री प्रभुभाई नागरभाई वसावा (बारदोली) : मेरे लोक सभा क्षेत्र बारदोली गुजरात से जा रही उद्यना-जलगांव (तापी रेलवे लाइन) पर महत्वपूर्ण तीन जगह पर रेलवे ओवर ब्रिज या अंडरपास नहीं होने पर लगातार अकस्मात् दुर्घटना हो रही है और ट्रैफिक जाम की समस्या से लोगों को बहुत तकलीफ उठानी पड़ रही है। इसलिए चलथान गांव के बीच में एल.सी. गेट नं. 13 पर अन्डरपास और बारदोली स्टेट हाइवे नं. 88 के गेट नं. 27 तथा व्यारा नेशनल स्टेट हाइवे नं. 56 के गेट नं. 51 पर शीघ्र ही रेलवे ओवरब्रिज बनाने के लिए मैं सरकार से मांग करता हूँ।

(iv) Need to include Mahar/Mahara caste of Chhattisgarh in the list of Scheduled Castes.

श्री विक्रम उसेंडी (कांकेर) : छत्तीसगढ़ राज्य में निवासरत महरा/माहरा जाति मूल रूप से महार जाति का एक उप समूह है जो छत्तीसगढ़ बोली में महरा/माहरा कहलाते हैं। सूती कपड़ा बुनना, कोटवारी इनका प्रमुख कार्य है। इस जाति का निवास छत्तीसगढ़ के धमतरी, रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, कवर्धा, बिलासपुर, महासमुंद, कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बीजापुर, जांजगीर-चाँपा, रायगढ़, सरगुजा आदि जिलो में हैं। छत्तीसगढ़ शासन आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य मंत्री परिषद के निर्णय अनुसार एवं आदिमजाति अनुसंधान संस्थान द्वारा महरा/माहरा जाति के सम्बन्ध में की गई अनुशंसा को स्वीकार करते हुए उक्त जाति का छत्तीसगढ़ राज्य की अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करने संबंधी प्रस्ताव भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय को दिनांक 8.5.2008 को प्रेषित किया गया। इस प्रस्ताव पर भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा अपने पत्र दिनांक 21.10.2008 में उल्लेख किया गया कि अविभाजित मध्य प्रदेश शासन द्वारा वर्ष 1989 में महरा जाति का प्रस्ताव समावेशन हेतु प्रेषित किया गया था जिसमें वर्तमान छत्तीसगढ़ राज्य की भौगोलिक सीमा में निवासरत महरा/माहरा परिवारों का अध्ययन किया गया जिसमें ओ.आर.जी.आई. द्वारा स्वीकार करने के उपरांत विभाजित मध्य प्रदेश राज्य की अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करने संबंधी अधिसूचना भारत सरकार द्वारा वर्ष 2002 में की गई है। छत्तीसगढ़ शासन आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा दिनांक 13 जून, 2016 को पत्र क्रमांक-एफ-10-66/2009/25/2 के माध्यम से संयुक्त सचिव, भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय को इस प्रस्ताव पर पुनर्विचार करते हुए समुचित कार्यवाही करने की अनुशंसा की गई है। इस जाति के लोगों को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल नहीं किये जाने के कारण इस वर्ग के लोगों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है तथा संवैधानिक लाभों से वंचित होना पड़ रहा है। कृपया शीघ्र ही उचित कार्यवाही की जाए जिससे इन वर्गों की वर्षों से लंबित समस्या का समाधान हो सके।

(v) Need to set up a super a Speciality Hospital/Polyclinic and six more CGHS Wellness Centres in Jabalpur, Madhya Pradesh.

श्री राकेश सिंह (जबलपुर) : जबलपुर शहर में केन्द्रीय कार्यालयों/संगठनों की संख्या लगभग 115 है। इसके अतिरिक्त रक्षा मंत्रालय की 4 बड़ी ऑर्डनेंस के साथ एम.ई.एस. एवं मिलिट्री बेस वर्कशॉप तथा सेंट्रल ऑर्डनेंस डिपो भी जबलपुर में कार्यरत हैं। तद्नुसार सी.जी.एच.एस. के अंतर्गत कार्यरत एवं सेवानिवृत्त कार्ड होल्डर रक्षा कर्मचारियों एवं आश्रितों की संख्या 85 हज़ार है।

इन 85 हज़ार लाभार्थियों को चिकित्सा सेवा प्रदान करने हेतु जबलपुर शहर में वर्तमान में सी.जी.एच.एस. के केवल 04 वेलनेस सेंटर उपलब्ध हैं। मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का जबलपुर की जनता की ओर से उनके जबलपुर प्रवास के दौरान एक अतिरिक्त वेलनेस सेंटर खोलने की घोषणा हेतु आभार व्यक्त करता हूँ। बावजूद इसके, लाभार्थियों की संख्या के अनुरूप जबलपुर में सी.जी.एच.एस. का एक मल्टी सुपर स्पेशियेलिटी अस्पताल या पॉली क्लीनिक तथा 06 अतिरिक्त वेलनेस सेंटर खोले जाने की अत्यंत आवश्यकता है।

वस्तुस्थिति यह है कि अन्य शहरों में प्रति वेलनेस सेंटर लाभार्थियों का औसत 03 हजार से 10 हजार के बीच है, जबकि जबलपुर में यह औसत प्रति वेलनेस सेंटर 22 हज़ार है। इस प्रकार प्रत्येक वेलनेस सेंटर में कार्यभार दो गुना है। इसके फलस्वरूप वरिष्ठ नागरिकों को घंटों कतार में रहना पड़ता है तथा सी.जी.एच.एस. में डॉक्टरों एवं स्टाफ की सीमित संख्या के चलते उन्हें उचित उपचार नहीं मिल पाता है।

प्रस्तुत आंकड़ों तथा सी.जी.एच.एस. से संबंधित भारत सरकार के उपलब्ध नियमों के अनुसार जबलपुर में लाभार्थियों को उचित चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के दृष्टिकोण से शहर में सी.जी.एच.एस. का एक मल्टी सुपरस्पेशियेलिटी अस्पताल या पॉली क्लीनिक तथा 06 अतिरिक्त वेलनेस सेंटर खोले जाने की अत्यंत आवश्यकता है। मैं आशा करूँगा कि सरकार इस ओर विशेष ध्यान देते हुए शीघ्रातिशीघ्र उचित निर्णय लेगी।

(vi) Need to construct a irrigation canal to channelise the water of Chandan dam to Godda, Jharkhand

SHRI NISHIKANT DUBEY (GODDA): The construction of Chandan Dam in Banka district of Bihar started in 1962 at the cost of Rs. 3 crore and was completed in 1978 at the cost of Rs. 12 crores. It can irrrigate 80 thousand hectares of Rabi and Kharif crops. Under this large scale irrigation project, there was a plan to build 105 Kilometre long canal of which 35 Kilometre of canal was to be in Bihar's Banka and the 70 Kms of canal in Jharkhand's Godda. The water from the dam was to reach Godda's Triveni, Kajhiya, Harna north and Harna south. It had to be connected to poriyahat's proposed Suggabathan dam. This was also to be the support of river Basin under Mahagamas like Sonepur, Bhaura, Rajabandh and Sunder reservoir. Santhal Pargana is affected by naxalism and terrorism. I request to help the farmers of Godda District, Jharkhand so that the farmers get the what is rightful which has been neglected from 1978. Once this canal is built, Godda district alone will be able to feed entire Jharkhand.

(vii) Need to ban TV serials depicting wrong portrayal of historical and mythological texts.

श्री सुधीर गुप्ता (मंदसौर) : इन दिनों टी.वी. चैनल्स पर अनेक पौराणिक एवं धार्मिक चरित्र पर आधारित धारावाहिक प्रसारित हो रहे हैं। किन्तु जनसंवाद एवं देखने में आया है कि कथित रोचकता एवं दर्शक संख्या बढ़ाने के लालच में निर्माता-निर्देशक तथ्यों को नजरअंदाज कर धार्मिक भावनाओं को आघात पहुंचा रहे हैं। मैंने इस संबंध में अनेक विद्वान जनों से चर्चा की एवं शास्त्रों का ज्ञान रखने वाले विद्वानों से सम्पर्क किया। धारावाहिकों में पौराणिक तथ्यों से होने वाली छेड़छाड़ पर सबने चिंता जाहिर की है। तथ्यों से छेड़छाड़ के चलते न सिर्फ समाज में गलत संदेश जा रहा है बल्कि नई पीढ़ी पौराणिक घटनाओं का गलत ज्ञान प्राप्त कर रही है। यह पूरा घटनाक्रम समाज की भावनाओं पर चोट है। अतएव मेरा सरकार से आग्रह है कि धार्मिक धारावाहिकों का प्रसारण करने वाले चैनल्स एवं निर्माताओं के लिए गाइडलाइन्स जारी कर तथ्यों से छेड़छाड़ पर सीरियल पर बैन जैसे प्रावधान किए जाएं एवं वर्तमान प्रावधान से अवगत कराने की कृपा करें।

(viii) Need to take immediate remedial steps to check soil erosion by rivers in various districts of Jharkhand particularly in Palamu and Garwha districts.

श्री विष्णु दयाल राम (पलामू) : मिट्टी के कटाव से संबंधित प्रकाशित एक सर्वे की रिपोर्ट जो भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केन्द्र (इसरो) की संस्था स्पेस एप्लीकेशन्स सेंटर, अहमदाबाद की अगुवाई में कराया है, के तथ्य चौंकाने वाले और चिंताजनक हैं। सर्वे में दर्शाया गया है कि झारखण्ड में पिछले आठ साल में 80 हजार हैक्टेयर भूमि मिट्टी के कटाव के कारण लगभग बंजर हो गयी है। इस भूमि की उपजाऊ मिट्टी की परत 15 सेंटीमीटर की बारिश और बाढ़ के कारण नालों और नदियों में बहती जा रही है। सर्वे के आधार पर तैयार रिपोर्ट में झारखण्ड प्रदेश के चार जिलों की स्थिति भयावह है जिनमें से मेरे संसदीय क्षेत्र अंतर्गत पलामू जिला भी है।

रिपोर्ट बताती है कि पलामू के कुल भू-भाग 8,02,291 हैक्टेयर में से 50,363 हैक्टेयर भूमि कटाव के दायरे में है। पलामू एवं गढवा जिलान्तर्गत न केवल उत्तर कोयल नदी, अमानत एवं सोन नदी से भीषण कटाव हो रहा है जिससे न केवल कृषि योग्य भूमि कट रही है, बल्कि मकान भी कटने शुरू हो गए हैं। जिससे लोग घर-बार छोड़कर दूसरी जगहों पर जा रहे हैं। खासकर उत्तर कोयल नदी के पूर्वी तट पर कादल गाँव से सलखनी तक, उटारी से मुहम्मदगंज तक, मुहम्मदगंज से भजनिंया पंचायत में एवं श्रीनगर का इलाका पूरी तरह से कटाव की चपेट में आ गया है और नदी का पानी कम होने पर खेती योग्य भूमि में बालू एकत्र हो रहा है। यदि समय रहते इस भूमि कटाव पर शीघ्र नियंत्रण के लिए प्रभावकारी कदम नहीं उठाये गये तो लोगों को विवश होकर बड़ी संख्या में पलायन करना होगा।

मानव सभ्यता को बचाए रखने के लिए मिट्टी के क्षरण को रोकना बेहद जरूरी है। 1000 साल लग जाते हैं मिट्टी की एक उपजाऊ परत बनने में।

मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि मिट्टी के कटाव जैसे संवेदनशील मुद्दे पर राज्य सरकार के साथ मिलकर जल्द ही कोई निर्णायक कदम उठाकर वर्तमान तथा संभावित समस्याओं को रोकने के लिए प्रयास शुरू करें।

(ix) Need to regularise the services of temporary labourers engaged by FCI Depot Ghevra, Delhi.

श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल (महाराजगंज) : मैं खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री जी का ध्यान भारतीय खाद्य निगम, दिल्ली के घेवड़ा डिपो में व्याप्त लापरवाही एवं मजदूरों के शोषण की ओर दिलाना चाहता हूँ। भारतीय खाद्य निगम में 1985 से कार्यरत 617 नैमित्तिक मजदूरों के नियमितीकरण के लिए 1991 में प्रबंधन और कर्मचारी यूनियन ने एक समझौता किया। समझौते के मुताबिक 1992 में सभी मजदूरों का चिकित्सा परीक्षण करवाया गया। चिकित्सा परीक्षण के उपरांत प्रबंधन ने 451 मजदूरों को नियमित कर दिया। बाकी बचे हुए मजदूरों को कहा गया कि आपको बाद में नियमित कर दिया जाएगा। बाकी बचे 166 मजदूर वहीं काम नैमित्तिक आधार पर आज तक कर रहे हैं। उन्हें प्रबंधन ने बिल्कुल ही भुला दिया जबकि सुप्रीम कोर्ट का भी निर्णय है कि समान काम का समान वेतन और सुविधा मिलना चाहिए। नियमितीकरण करने में भी वरीयता का ध्यान नहीं रखा गया। प्रबंधन ने वरीयता क्रम को ध्यान में न रखकर मजदूरों को नियमित कर दिया। मजदूरों के पूछने पर वे सही जवाब भी नहीं देते हैं।

अतः हम मंत्री जी से मांग करते हैं कि इस मामले की जांच कराकर मजदूरों को न्याय दें। बाकी बचे हुए मजदूरों को भी नियमित करने का आदेश दें ताकि इन गरीबों को न्याय मिले। इनके और इनके बच्चों का भी जीवन स्तर इस महंगाई में ऊपर उठा सके।

(x) Need to construct a Road Over Bridge between Hazaribagh Road railway station and Keshwari railway station in Kodarma Parliamentary constituency, Jharkhand.

श्री रवीन्द्र कुमार राय (कोडरमा) : मेरे संसदीय क्षेत्र कोडरमा (झारखण्ड) अंतर्गत हजारीबाग रोड़-केश्वरी रेलवे स्टेशनों के बीच उपरी सड़क पुल का निर्माण काफी वर्षों से लंबित है। इस ओवर ब्रिज से संबंधित सभी औपचारिकताएं पूर्ण हो चुकी हैं। राज्य और रेलवे विभाग का पैसा भी आपस में निर्धारित हो चुका है। लेकिन वर्षों बीत जाने के बाद भी पुल का निर्माण कार्य अभी प्रारंभ नहीं करवाया गया है। प्रतिदिन यहाँ लम्बा जाम लगता है, इस पुल के न होने से जनता को काफी असुविधा हो रही है।

मेरा माननीय रेल मंत्री जी से अनुरोध है कि अविलम्ब इस ओवर ब्रिज का निर्माण करवाने हेतु संबंधित को निर्देशित करें।

(xi) Need to bring a policy to monitor the working of labour contractors

SHRIMATI RAKASHATAI KHADSE (RAVER): In almost all sectors, casual workers on daily wage basis by labour contractors are deployed not only in Public Sector Undertakings, Manufacturing Units, Banks but even to large extent in private companies including Small and Medium Industries. It has been learnt that there are many contractual workers working in PSUs and Banks carrying out the work of Clerks, Stenos etc. These labours are on contract basis on the pay roll of labour contractors. there are no stringent rules and regulations for the labour contractors and no mechanism has been established to keep a check on these labour contractors. These labour contractors are exploiting the labourers by not paying overtime allowance for 12 to 15 hrs of daily duty with no weekly holiday. There are large number of Security Guards facing the same consequences while performing night duties and are not being paid the night allowance with other necessary contents which are compulsory for them like uniform dress, shoes, belt and cap etc. including medical allowance, ESIC facility, PF and other social security benefits. These contractors are managing the tenders and every time by changing the name of the firms on rotation. Even these contractors have established relations with the top officers working on key positions and often please them by illegal means. I request Hon'ble Minister to bring a new policy for labour-oriented employment by making the organisations to appoint the staff and labour other than their permanent staff. Further, there is a need to examine working of the labour contractors and quickly establish guidelines held responsible for any lapse proved against the labour contractor. If need be, labour laws may also be changed/amended accordingly so that these contractors stop exploiting the contract labourers.

(xii) Need to develop public infrastructure conducive to differently-abled people in the country.

डॉ. वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़) : आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की पहल पर देश के स्वतंत्र होने के 69 वर्षों बाद पहली बार दिव्यांगजनों की सरकार द्वारा सुध ली गई है। आज तक देश में दिव्यांगजनों के लिए जितने कायदे-कानून बने हैं, उनमें कोई न कोई खामियां अवश्य रही हैं, जिसके कारण दिव्यांगों की स्थिति और परेशानियां जस की तस बनी हुई हैं। यह बेहद दुखद है कि देश में दिव्यांगों की अनदेखी इतने बड़े स्तर पर की जा रही है तथा शारीरिक रूप से अक्षम लोगों के लिए जन सुविधाओं का प्रावधान किया गया है, उनमें से ज्यादातर कागजी हैं। ये बात हाल ही में एक्सेसिबल इण्डिया के तहत देश में किए गए ऑडिट में खुलकर सामने आई हैं।

विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार दिव्यांगता से ग्रस्त लोगों को विविध किस्म की वंचनाओं को झेलना पड़ता है। दिव्यांगजनों के परिवार औसत से अधिक गरीब होते हैं तथा उनके पास सम्पत्ति के साधन भी कम होते हैं। दिव्यांगों के लिए सुविधाओं की कमी और उनके प्रति उपेक्षा भाव के चलते बहुत सारे दिव्यांग बच्चे प्रारम्भिक शिक्षा तक प्राप्त नहीं कर पाते। जो दिव्यांगजन रोजगार के अवसर पा भी जाते हैं, वे कार्य स्थलों पर रोजमर्रा की असविधाएं झेलने को मजबूर होते हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के प्रोत्साहन एवं दिव्यांगों के प्रति उनके गहरे सरोकार के कारण ही दिव्यांगों ने अंतर्राष्ट्रीय खेलों में अपने हुनर का लोहा पूरी दुनिया को मनवाया है।

ऐसे में मेरा सरकार से आग्रह है कि देश के दिव्यांगजनों को एक गरिमापूर्ण जीवन देने के लिए एक ऐसा ढांचा तैयार किया जाए, जिसमें दिव्यांगजनों को सार्वजनिक स्थलों पर किसी प्रकार की असुविधा न हो और वे भी अपने ज्ञान व गुणों से देश के विकास में अपना भरपूर योगदान दे सकें।

(xiii) Need to start work on the North-South Corridor of Diamond Quadrilateral Railway Project to establish high speed railway network in the country.

श्री प्रहलाद सिंह पटेल (दमोह) : मध्य प्रदेश जैसे राज्य के बुंदेलखण्ड, महाकौशल एवं विंध्य में रेल मार्गों की कमी है, अनेक सर्वे जैसे जबलपुर-पन्ना-दमोह, खजुराहो-भोपाल, श्रीधाम से रामटेक उपलब्ध है। लेकिन उन पर कार्य आगे नहीं बढ़ सका है। इन सर्वे में सबसे महत्वपूर्ण रेल क्षेत्र की हीरक चतुर्भुज योजना का उत्तर से दक्षिण को जोड़ने वाला मार्ग भी बुंदेलखण्ड के ललितपुर (उ.प्र.) से रामटेक (महाराष्ट्र) वाया सागर-नरसिंहपुर जिलों से होकर गुजर सकता है। एन.डी.ए. के घोषणापत्र एवं सरकार के गठन के बाद रेल का हीरक चतुर्भुज बनाने का संकल्प व्यक्त किया गया था। अतः रेल के हीरक चतुर्भुज में उत्तर से दक्षिण की दूरी कम करने वाली यह योजना अतिशीघ्र प्रारंभ हो ऐसी भारत सरकार से मांग है।

(xiv) Need to declare and develop the Sindkhed Raja, the birth place of Rajmata Jijau-mother of Chhatrapati Shivaji- in Buldhana district, Maharashtra as a historical place of international importance.

श्री राजीव सातव (हिंगोली) : मैं केन्द्र सरकार से छत्रपति शिवाजी महाराज की राजमाता जीजाऊ के जन्मस्थल सिंधखेड राजा जिला बुलढ़ाणा, महाराष्ट्र को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्मारक स्थल बनाने की मांग करता हूँ।

हिन्दवी स्वराज्य की जननी एवं छत्रपति शिवाजी महाराज की माता होने के साथ-साथ राजमाता जीजाऊ उनकी मार्गदर्शक और प्रेरणास्रोत भी थीं। उनका सारा जीवन साहस और त्याग से भरा हुआ था।

राजमाता जीजाऊ ने जीवन भर कठिनाइयों और विपरीत परिस्थितियों को देखते हुए भी धैर्य नहीं खोया और अपने पुत्र "शिवा " को वे संस्कार दिए, जिनके कारण वह आगे चलकर हिंदवी स्वराज के संस्थापक "छत्रपति शिवाजी महाराज " बने।

राष्ट्रमाता जीजाऊ का जन्मस्थल सिंधखेड राजा जिला बुलढ़ाणा, महाराष्ट्र के लिए पुण्यभूमि, शिवतीर्थ व मातृतीर्थ है। महाराष्ट्र की समस्त जनता के लिए यह ऐतिहासिक प्रेरणादायी धरोहर है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि राजमाता जीजाऊ के जन्मस्थल सिंधखेड राजा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्मारक का दर्जा दिया जाए और उसके लिए 1100 करोड़ की राशि उपलब्ध की जाए।

(xv) Need to provide financial assistance to Karnataka affected by drought

SHRI S.P. MUDDAHANUME GOWDA (TUMKUR): The State of Karnataka has been subjected to severe drought successively for the last six years. This year deficit and scarcity in rainfall has put the State in very bad condition. This year, 139 Taluks out of 176 Taluks in the State are declared as drought affected Taluks. This has caused huge economic loss to the State in general and agrarian community in particular. Deficit rainfall consecutively for more than six years have resulted in very poor or no storage in minor irrigation tanks and also depletion of groundwater level in the State which is an important source for drinking water for rural population and livestocks.

the total estimated loss due to drought in the State is Rs. 17,193 crores. The central team has also studied the ground realities. Government of Karnataka has sought assistance from the Union Government under NDRF to the tune of Rs. 4,702.54 crores, in addition to special assistance of Rs. 967.76 crores.

Hence, I urge upon the Union Government to sanction the financial assistance sought by the Government of Karnataka under NDRF to the tune of Rs. 4,702.54 crores and special assistance of Rs. 967.76 cores to the Karnataka State immediately and save the lives of the poor people in the State.

(xvi) Need to provide financial support to Solar Pump programmed in North Eastern States

SHRI GAURAV GOGOI (KALIABOR): In December 2014 the Indian Government launched a credit-linked back ended capital subsidy scheme (through NABARD) to be implemented for promotion of installation of solar pumpsets. The scheme involves provision of loans by commercial Banks, RRBs, State and District Central Cooperative Banks, SCARDBs and NABARD (under direct lending) for installation of Solar PV Pumping systems for the purpose of irrigation with provision of capital subsidy.

Given the vulnerabilities of the Northeast India, I would like to place the following demands for better implementation of the Solar Pump Program:-

Special Category Region for Northeast India- Northeast India has lower solar irradiance compared to the rest of the country. therefore, more effort is needed to promote solar power usage. Ministry of New and Renewable Energy has already considered Northeast India as special category states in the Solar Rooftop Program under NABARD Scheme.

Rise in Subsidy allocation- As the scheme targets small and marginal farmers in Northeast India the demand for solar pump must be encouraged. Currently the subsidy for the Solar Pump scheme is 30%-35% which is too low. the Solar Rooftop Program has a subsidy component of 70%. The low subsidy and the additional cost of solar pump and interest on loan amount makes the Solar Pump program unviable in its current design.

It is strongly recommended to give special support to Northeast India to ensure that the scheme reach out to the small and marginal farmers in a sustainable manner.

(xvii) Need to develop tourism infrastructure in Sirumalai Hills near Dindigul in Tamil Nadu

SHRI M. UDHAYAKUMAR (DINDIGUL): Sirumalai Hills covers about 60,000 acre and ranges about 1600 metres from sea level and is 25 Kms. from Dindigul town. It also has a water stream which is an attraction for tourists and view point to view full Dindigul City, Rockfort of Dindigul and Madurai city.

There is a huge scope in developing this Sirumalai as similar or more than that of Ooty and Kodaikanal in Tamil Nadu. Keeping in mind the Government of Tamil Nadu headed by Puratchi Thalaivi Amma planned to develop Sirumalai hill near Dindigul in a big way by the Tamil Nadu Tourism Department Corporation. It has drawn up a plan to establish a big botanical garden sprawling over 10 acres on the lines of Bryant Park in Kodaikanal and would have all native species. A 35 acre land under the control of Sericulture Department has been identified for developing facilities for tourists.

The Tamil Nadu Generation and Distribution Corporation Limited (TANGEDCO) is going to establish a substation to ensure uninterrupted power supply to the park and areas around it.

I urge upon the Ministry of Tourism to extend a helping hand to the Tamil Nadu Government in developing the Sirumalai Hills as a tourist spot by providing assistance from Tourism Infrastructure Development Fund. The following infrastructure development may be done by the Central sector scheme.

- Constructing a telescope house from tourist point of view.
- Setting up Organic farms as in other Hill stations.
- Rope car facilities may be provided for the tourists.

I also request the Central Government to include Tamil Nadu Government in 'Hunar Se Rozgar Tak' programme.

(xviii) Need to construct a service Road on National Highway No. 45 at Samayapuram village in Perambalur Parliamentary Constituency of Tamil Nadu

SHRI R.P. MARUTHARAJAA (PERAMBALUR): The Samayapuram village falling under the jurisdiction of Perambalur Lok Sabha Constituency is visited by lakhs of devotees from across the state for its famous temple town. Due to lack of a service road on this stretch, the devotees and the local administration have been facing hardship in particular during the festive season during April-May when lakhs of devotees assemble here. The four lane stretch between Padalur-Trichy Section on National highway No. 45 has been under the O & M stage and due to this many accidents take place and the people have to drive/walk a long distance for coming to the Samayapuram village.

Keeping in mind the dire necessity of providing a service road to the Samayapuram Village and also the hardship faced by the public at large, I urge upon the Government to give top priority to redress the grievance and fulfill the long pending demand of the people of my constituency and issue necessary orders to concerned authorities for providing a service Road to Samayapuram village.

(xix) Need to bring normalcy along the Line of Control

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): The situation on the LoC in J&K is very serious. The day after killing of 3 Indian soldiers, India opened fire on LoC which killed 12 Pakistanis. Pakistan has said it lost 3 army personnel including a Captain, while 9 civilians were killed when Indian fire hit a bus on the Neelum Valley road on the Dudhnial sector in PoK. India accused Pakistan for opening fire on civilian target on the sectors of Machil, Keran and Gurez on 23.11.2016. The Indian DGMO spoke to his Pakistan counterpart on hotline following a Pakistan request. The violence on the LoC has escalated sharply after the surgical strikes on 28 September with 12 Military Personnel and 12 Civilians recorded to have been killed till 15 November. Infiltration attempts by terrorists and militants on India have escalated the issue. Urgent steps both diplomatic and military are needed to bring normalcy in LoC area.

(xx) Need to provide remunerative price of paddy and jute to farmers in West Bengal particularly in Krishnanagar Parliamentary Constituency

SHRI TAPAS PAUL (KRISHNANAGAR): Over the last 15 years over 2 lakh farmer have committed suicide in different parts of the country due to an acute agrarian crisis. West Bengal which is otherwise blessed with very fertile soil, agriculture has also been very badly affected by a spate of farmers suicides in the recent years. One of the main reason for the crisis is that the farmers are getting very low rates for the paddy and jute crops in Krishnanagar Parliamentary Constituency, West Bengal. There is a need to look into this matter urgently so that this unhealthy trend of farmers suicides in the state of West Bengal can be reversed.

(xxi) Need to declare Malkangiri district in Odisha as a Japanese Encephalitis Vaccine District and start timely vaccination in the district

SHRI BALBHADRA MAJHI (NABARANGPUR): Japanese Encephalitis outbreak in Malkangiri District of Odisha has already caused death of more than 100 children. The occurrence of Japanese Encephalitis was first reported in 2012. Since then Government of Odisha has been requesting the Central Government to include Malkangiri as a Japanese Encephalitis Vaccine District but Centre is yet to do the same. Timely vaccination of children could have saved these innocent lives.

It is, therefore, urged upon the Central Government to declare Malkangiri as Japanese Encephalitis Vaccine District and start timely vaccination.

(xxii) Need to implement the Coastal Regulation Zone (CRZ) Notification, 2011

SHRI GAJANAN KIRTIKAR (MUMBAI NORTH WEST): The coastal Regulation Zone (CRZ) Notification 2011 enshrines the concept of a Coastal Zone Management Plan (CZMP). It will be prepared with the fullest involvement and participation of local communities. What is the definition of the 'No Development Zone'? The " no development zone" definition has been changed. It is reduced from 200 meters from the high-tide line to 100 meters only. This has been done to meet increased demands of housing of fishing and other traditional coastal communities. Importance of CRZ Notification in India becomes all the more important since our country has a long coastline of 7516 km. Our coastal ecosystems provide protection from natural disasters such as floods and tsunamis to the 250 million people who live in our coastal areas. Coastal waters provide a source of primary livelihood to 7 million households. Our marine ecosystem is a treasure trove of biodiversity, which we are only beginning to discover and catalogue. Thus, our coastline is both a precious natural resource and an important economic asset, and we need a robust progressive framework to regulate our coast.

Therefore, I urge upon the Ministry of Environment, Forest and Climate Change to implement to the CRZ Notification, 2011 immediately.

(xxiii) Need to provide financial assistance to cooperative sugar factories in Andhra Pradesh

SHRI MUTHAMSETTI SRINIVASA RAO (AVANTHI) (ANAKAPALLI): In my State Andhra Pradesh 80 per cent of sugarcane cultivators under the Cooperative Sugar industries are small and marginal farmers. They grow sugarcane in their small holding and leased land from big farmers. Due to vagaries of monsoon, payment of higher lease rates, high cost of labour, non availability of labour (MGNREGA), higher cost of harvesting and transportation, growing sugarcane is not remunerative leading to decreased cane area and lower cane availability for crushing to run the sugar industry for a minimum duration of 130 days.

The cooperative sugar factories were established for the betterment of the livelihood of farming community in the State; and to provide employment for the rural folk to uplift their standard of living. With this ambition about 16 cooperative sugar industries were established. Out of this only 10 cooperative sugar industries are existing and out of these only six cooperative sugar industries are working with a lot of financial and technical problems. Out of six sugar industries, four industries come under my Anakapalle Parliamentary Constituency. They are Etikoppaka, Govada, Thandava and Thummapala.

With the launch of MGNREGA Programme, the only major crop affected is sugarcane as there is acute scarcity of labour. It coincides with sugarcane cultivation.

Due to lower realization from the sale of sugar and other byproducts, cane payments are not being made in full to the tune of FRP; and also transport incentives which were promised to the cane suppliers have not been made so far.

Therefore, I urge upon the Government to provide financial assistance to clear sugarcane price dues as grant; to provide financial assistance and continuation of grant of 40 per cent SDF loans to install co-generation facilities in all the co-op sugar factories to improve revenue generation; to fix sugar price at a minimum of 3,500 per quintal of sugar excluding taxes and to link up sugarcane crop with MGNREGA scheme to make available labour for the cultivation of the crop which coincided with this programme.

(xxiv) Need to hand over the land occupied by Assam Rifles Complex to the State Government of Tripura for setting up of a multi-discipline Sports and Cultural Complex

SHRI JITENDRA CHAUDHURY (TRIPURA EAST): Assam Rifles Complex in Tripura is situated on the heart of the Agartala city. In Tripura, Assam Rifles are having hardly any presence, except one or two Training Battalion, as the State's law and order situation is mainly maintained by its own forces (Tripura Police and Tripura State Rifles) besides the CRPF and BSF. Hence, the large area occupied by the Assam Rifles, since long be vacated and handed over to the State Government for the purpose of setting up of a multi-disciplined Sports and Cultural Complex. The Citizens Forum and Sports lovers of the State have already been agitating on the issue for long. Echoing to this popular demand, Government of Tripura has also taken up the issue with the Government of India and offered alternative land to Assam Rifles in vicinity of the Agartala city. Now, the Ministry of Home Affairs may consider the case with immediate effect.

(xxv) Need to establish a 50 bed AYUSH Hospital in Hisar, Haryana under National AYUSH Mission

SHRI DUSHYANT CHAUTALA (HISAR): Nowadays, the importance of Indian system of medicines has widely been recognized at all level which insist us the need for development of traditional medicines. In this connection, I would like to urge the Government for setting up of a 50-bedded AYUSH Hospital in Hisar under National AYUSH Mission. The city of Hisar is one of well developed city comprised with a number of Central Government institutions, universities, business centers. The number of floating population is highest since people are visiting from Punjab, Rajasthan and other parts of the state to Hisar every day. Therefore, there is a need for setting up a 50-bedded AYUSH Hospital in Hisar under National AYUSH Mission. In case of establishment of such hospital, it would be more beneficial to the entire state of Haryana as well as other neighbouring States i.e. Punjab and Rajasthan and I request the government to take necessary action accordingly.

(xxvi) Relaxation in restrictions imposed by Archaeological Survey of India for undertaking new construction/repair of houses in Thrissur district of Kerala

SHRI C.N. JAYADEVAN (THRISSUR): In Kerala there are 26 Central monuments and 116 State monuments and out of this, majority are in Thrissur district. Many of them are temples. People are living in the vicinity of these temples. People are living in the vicinity of these temples for years. As there is a restriction imposed by Archaeological Survey of India for new constructions within the vicinity of 200 metres to these monuments, particularly temples, the people residing within this area are not able to even reconstruct their own houses which are in dilapidated condition. The land owners in and around this area could not undertake any repair or reconstruction works for protection of their existing structures because of this restriction. Even the temples are not able to undertake new constructions for the convenience of the devotees. I, therefore, urge upon the Government to make some relaxation in the restrictions imposed by ASI to relieve the hardships to the common people and dwellers in the area.

HON. CHAIRPERSON: The House stands adjourned to meet again at 2.30 p.m.

14.03 hours

The Lok Sabha then adjourned till Thirty Minutes past Fourteen of the Clock.

14.31 hours

The Lok Sabha reassembled at Thirty One Minutes past Fourteen of the Clock.

*(*Hon. Speaker *in the Chair)*

…(व्यवधान)

TAXATION LAWS (SECOND AMENDMENT) BILL, 2016

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : मैडम स्पीकर, मैं कहना चाहता हूँ ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : नया क्या है?

…(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: एडजर्नमैंट मोशन लीजिए। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : नहीं नहीं, इसके अलावा नया कुछ हो तो बताइए। If you are talking about Adjournment Motion, I am sorry. If there is anything new, I will allow. …

(*Interruptions*)

HON. SPEAKER: I have given my ruling on that. So, again and again talking about Adjournment Motion is not allowed. If any new thing is there, I will allow you and that too for 30 seconds only. दो मिनट वगैरह नहीं होता है।

…(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Otherwise we will take the Bill.

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: मैडम स्पीकर, यह इंपॉर्टैन्ट इसलिए है कि हम भी समय व्यर्थ नहीं करना चाहते हैं। आप स्ट्रेटअवे अगर एडजर्नमैंट मोशन को परमीशन देते हैं तो निश्चित रूप से डिसकशन चलेगा।

HON. SPEAKER: I have given my ruling.

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: उसमें यह बिल भी डिसकस करेंगे। इस बिल में भी जो है, वह उसी में मिलकर डिसकस करेंगे। इसीलिए आप एडजर्नमैंट मोशन को लीजिए। ...(व्यवधान) Bill will also be discussed.

HON. SPEAKER: I have given my decision.

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: उसमें कहाँ कमियाँ हैं, कहाँ-कहाँ उनकी गलतियाँ हैं, कैसे उनको सुधार सकते हैं, वह देखना है। आज देश इतना परेशान है कि 80 के ऊपर लोग मर चुके हैं, सैकड़ों लोग घायल हो चुके हैं।

इसीलिए जो आप बिल के बारे में बोल रहे हैं, अगर एडजर्नमैंट मोशन के लिए परमीशन देते हैं तो दोनों को मिलाकर कर सकते हैं। ...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: How can we take both these things?

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: उस पर भी वोटिंग होनी चाहिए और इसके लिए भी वोटिंग होनी चाहिए। इसीलिए अगर दोनों को मिला दें. ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : बिल के अमैंडमैंट पर तो वोटिंग होनी ही है।

...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: अगर दोनों का संगम होगा तो नैचुरली यह बिल भी पास हो जाएगा और हमारा डिसकशन भी होगा। ...(व्यवधान)

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री अनन्तकुमार): अध्यक्ष जी, मैं खड़गे जी से इतना ही कहना चाहूँगा कि एडजर्नमैंट मोशन के बारे में अपनी राय हम कह चुके हैं। हम बहस के लिए तैयार हैं और आप कृपया बिल ले लीजिए। ...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: I have given my decision.

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY (KOLKATA UTTAR): The Bill was introduced. We are not prepared yesterday to study it either. It was a very hasty decision and it was circulated amongst us. It has already been declared by the Central Government official that it is going to be implemented within 15th of the next month. It is already out. Though the Bill is under consideration, it is already exposed that what the purpose of the Government is. … (*Interruptions*) So, what I would propose is to consider these two – this Bill, this Motion and the demonetization issue - can be clubbed together, then discussion can start.

HON. SPEAKER: No, this Bill cannot be clubbed with Adjournment Motion. …

(*Interruptions*)

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY : No Madam, it can be clubbed. This is a part of the demonetization issue. It is a follow up step. It is not coming up separately. It is a follow up reflection.… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: While discussing this Bill, you can say whatever you want to say.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Madam Speaker, the Taxation Law (Second Amendment) Bill is a very important Bill. It deals with the Taxation law, amendment to the Income Tax Act and it has serious repercussions on the Taxation Policy of the country. But, in all urgency, it was brought yesterday. It was not listed. Today it is listed for consideration and passing. We have moved some amendments. Shri Premachandran has moved some amendments. Shri Rajeev Satav has moved some amendments. But these are all amendments of a very technical nature. I was going through the Bill. It needs some more improvement, and I think, the Finance Minister will agree that whatever deliberations will be done in this House will always improve the structure of the Bill. But before we come to the Bill, the House has to be in order and for that, it is necessary that from our Party, our Chief Minister has welcomed.… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: One minute please.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : Our Chief Minister and our Party have welcomed the demonetization policy. There have been some flaws or some difficulties on the implementation part. We also, therefore, demand a deliberation, a discussion relating to that issue. Therefore, Madam, first let us take up the discussion on demonetization issue and then we can have a structured deliberation on the Taxation Laws (Second Amendment) Bill, which is necessary. It is because there are two issues. … (*Interruptions*)

Very rightly, I would request Shri Sudip Bandyopadhyay also. One is the demonetization issue and another is the taxation policy attacking black money. Cutting across party lines, all the political parties in this House are against the scourge of black money. The respective Governments, be it the previous Government or be the Atal Ji's Government from 1998-2004—all had spoken and acted against black money. When Dr. Saheb was there as the Prime Minister, he had also taken lot of initiatives to attack black money. And, if this Bill is attacking black money, I think there would be no hesitation from any quarter to stop or delay this Bill. But first let us take up the demonetization issue in whatever form it

may be. If all the leaders agree, we can work out on the Motion on which we can discuss, and voting can also take place. … (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Yes, Jaitley Ji.

… (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : सबको बोलने की आवश्यकता नहीं है, बात सामने आ गई है।

…(व्यवधान)

HON. SPEAKER: No, everybody will not say something.

… (*Interruptions*)

SHRI P. KARUNAKARAN (KASARGOD): You can listen to the Communist Party…. (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: I have already called him. I know your view. It is all right. Let him speak.

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: From your Party, Shri Sudip Bandyopadhyay has explained.

… (*Interruptions*)

SHRI K.C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): Madam, I am raising a point of order…. (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: No, not now.

… (*Interruptions*)

SHRI K.C. VENUGOPAL: Madam, I am raising a point of order. … (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: No, please.

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Only Jaitley Ji's speech will go on record.

… (*Interruptions*) ... *

HON. SPEAKER: Under what rule? No, there is no point of order. What is it?

… (*Interruptions*)

---

* Not recorded.

HON. SPEAKER: Arun Jaitley Ji, you can go on. I have allowed you.

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: No, I am sorry.

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: I will listen to your point of order. What is it?

… (*Interruptions*)

वित्त मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्री (श्री अरुण जेटली) : आप प्वाइंट ऑफ आर्डर एलाऊ कर दीजिए, मैं जवाब दे देता हूं। ...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: All right, under what rule are you raising the point of order?

… (*Interruptions*)

SHRI K.C. VENUGOPAL : Madam, as per rule 81, I am raising a point of order.

Here the hon. Minister has risen and today's List of Business has also stated that an IT (Amendment) Bill is going to be taken up for consideration and passing today itself. We moved amendment within a short span of time. The time of amendment has to be before 12 o' clock. Already, I have moved an amendment and that was accepted by the Government also. But for that amendment there is a need for the President's assent. I moved the amendment at 12 o' clock. Then, the Government printed it at 12.30 p.m. How can the President's assent be given within a short span? That means, anticipating the President's assent, the President has been brought here controversially. Is it possible to obtain the President's assent within a span of one hour? Hon. Finance Minister, is it possible? That means, you are bulldozing an important law without any homework. … (*Interruptions*) Therefore, this should be postponed.… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Saugata Roy ji, do you want to raise a point of order? Please mention the Rule number.

… (*Interruptions*)

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): I want to raise a point of order under Rules 72, 74, 75 and Articles 117 and 274 of the Constitution of India. … (*Interruptions*)

Madam, I am talking about the Taxation Laws (Second Amendment) Bill, 2016. Yesterday, at 2 o'clock, while there was din and turmoil in the House and when the Members protesting against demonetization, the Finance Minister came ...* and introduced the Bill. … (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: What word is it? I do not know. What is the word?

… (*Interruptions*)

PROF. SAUGATA ROY: It is ...* It is not unparliamentary.… (*Interruptions*)

SHRI ANANTHKUMAR : ... * is a wrong word. It has to be expunged.… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Okay, I will see it. Please do not use this word.

… (*Interruptions*)

PROF. SAUGATA ROY : May I use the word stealthily or may I use another word furtively … (*Interruptions*) So, he introduced the Bill furtively. … (*Interruptions*) Please listen to me. … (*Interruptions*)

Normally what happens when a Bill is to be brought, it is included in the List of Business. In yesterday's List of Business the Taxation Laws (Second Amendment) Bill was not there. If it was there, then we would have moved opposition to the introduction under Rule 72(1). But we were deprived of that basic opportunity of opposing the introduction of an anti-people Bill. Anyway, that happened.

Then, what is the next stage in the Bill? The second stage is that the Bill may be taken into consideration under Rule 74. Then, under Rule 75, there may be a discussion on the principles of the Bill. Madam, as you know, the House has been in turmoil since 16th of November. Everyday you have to adjourn the House three to four times. Now, this is a Bill, which affects the Government's misguided efforts on demonetization, black money, etc. This is a follow-up of the Government's decision to demonetize Rs.500 and Rs.1000 notes. The House has

* Not recorded.

been in a total turmoil. All of us in the Opposition Benches vocally oppose the decision of the Government. … (*Interruptions*)

All I want to say is that in such an important Bill, the Finance Minister is proposing a Pradhan Mantri Garib Kalyan Kosh to give a special opportunity to black money holders. This is a serious matter.… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: You are talking about the Bill. You have started the discussion. … (*Interruptions*)

PROF. SAUGATA ROY: I will not talk on the Bill. … (*Interruptions*) Madam, this Bill should be discussed in all seriousness with full-fledged deliberation. As you know, when it was being discussed in the Business Advisory Committee, the Government wanted only two hours for discussion.… (*Interruptions*)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: Let us not discuss it here.… (*Interruptions*)

PROF. SAUGATA ROY: Okay, we will not discuss it. … (*Interruptions*)

Now, another very vital point was mentioned by Mr. Venugopal. … (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Please conclude.

PROF. SAUGATA ROY: Madam, it is not over.… (*Interruptions*)

Under Articles 117 and 274 of the Constitution, before bringing the Bill, the President's recommendation has to be obtained. The Minister must have obtained the President's recommendation. Now, we are putting amendments for the same. Then, for the amendments to be fruitful, again the President's assent is necessary under Articles 117 and 274. All I want to say is that for a proper and structured discussion on the Government's misguided efforts to curb black money through this Bill, it is necessary that the House be in perfect order and the House can be in perfect order after we have discussed the demonetization issue through an adjournment motion. Unless that happens, discussion on this Bill … (*Interruptions*) The plan of the Government is, again, furtive. They are trying to pass the Bill in the din. The Minister will read and there will be 'ayes'. … (*Interruptions*) Madam, this should not happen. The future of the nation is at

stake. This Government's effort of no discussion on the Bill should not be allowed. We should have a proper discussion. … (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: That is okay now.

PROF. SAUGATA ROY: Madam, you are the custodian. … (*Interruptions*)

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT, MINISTER OF HOUSING AND URBAN POVERTY ALLEVIATION AND MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI M. VENKAIAH NAIDU): Madam Speaker, what is his point of order? … (*Interruptions*) The Business says … (*Interruptions*) The House is in turmoil because of them. … (*Interruptions*) Do not waste the time of the House like this. … (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Shri N.K. Premachandran.

… (*Interruptions*)

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Madam Speaker, thank you very much. … (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Do you want to say the same thing?

SHRI N.K. PREMACHANDRAN : No, Madam. I am on a different point.

HON. SPEAKER: Please tell the Rule Number.

SHRI N.K. PREMACHANDRAN: Madam, I thank you very much for allowing me to make my point of order. My point of order is under Rule 376 and Rules 81 and 82. Shri K.C. Venugopal has already talked about Rule 81. So, Madam, kindly go through Rule 82. The order of the President granting or withholding the sanction or recommendation to an amendment to a Bill shall be communicated to the Secretary General by the Minister concerned in writing.

Madam, my point is that I have given notices for seven amendments. Out of these seven amendments, five amendments require the recommendation of hon. His Excellency, the President. I would like to know from the hon. Finance Minister whether the recommendation in writing has been obtained from His Excellency, the President of India, so that I am getting the opportunity to move my

amendments. That should be communicated in writing - whether it is withheld, whether it is assented or whether it is rejected. That is my first objection.

My second objection is that going to the Bill, kindly see section 199(C) of the Bill, that is, clause 3.

HON. SPEAKER: No, you cannot speak about the amendment.

SHRI N.K. PREMACHANDRAN: No, I am not going into the merit and I am not going to the amendment.

HON. SPEAKER: You are talking about the Bill. No, I am sorry.

SHRI N.K. PREMACHANDRAN: Madam, I may be allowed. Let the hon. Finance Minister reply.

Madam, yesterday the Revenue Secretary has unequivocally spoken before the Press that December 30th will be the last day for availing the benefit under it. … (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: No, that is another thing. You have given the motion for another thing.

SHRI N.K. PREMACHANDRAN: Madam, on this point of order, I am seeking a ruling.

Thank you very much.

HON. SPEAKER: Thank you very much.

Shri Arun Jaitley.

… (*Interruptions*)

श्री अरुण जेटली : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने टैक्ससेन अमेंडमेंट बिल, 2016 जैसे महत्वपूर्ण विषय पर ...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: That, I will.

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: One thing is there that you have talked about the amendment. Let the amendment come. At that time, I will give the ruling. I am not saying 'no'.

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: No, I am sorry.

Another thing is 'bring the House in order'. You have to do that. I am requesting you that this is an important Bill and therefore, please keep the House in order.

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: At the time of consideration of the Bill, I will definitely do it.

… (*Interruptions*)

SHRI ARUN JAITLEY: Madam, the Bill has already been introduced yesterday. … (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: I am sorry. The Bill has already been introduced.

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: You have to keep order in the House. I am requesting you all to let the House be in order so that we can discuss the Bill.

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: No, I am sorry. This is an important Bill and an urgent one.

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: At that time only, I will give my ruling.

Yes, hon. Minister.

… (*Interruptions*)

SHRI MOHAMMAD SALIM (RAIGANJ): Madam, this will go down as a black day in the history of Parliament. … (*Interruptions*)

Madam, … (*Interruptions*)

SHRI ARUN JAITLEY: Madam, I am sorry. This is a serious aspersion against the Chair. … (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: No, I am sorry.

… (*Interruptions*)

SHRI MOHAMMAD SALIM: Madam, you are the custodian of the whole House. … (*Interruptions*)

14.50 hours

(*At this stage, Shri Kanti Lal Bhuria, Prof. Saugata Roy, Shri Mohammad Salim and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.*)

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Madam, he has made comments against the Chair. … (*Interruptions*)

I am sorry that he has made an aspersion against the Chair. That is what I am saying. This Bill was introduced yesterday. It is there in the agenda of the House. The Chair had allowed it. How can they raise an objection? They do not have the numbers. … (*Interruptions*) They have disturbed the House from 17th till today. … (*Interruptions*) They are wasting the time of the country and also the people. … (*Interruptions*) This is a very important Bill. … (*Interruptions*) Let them go to their seats; take part in the debate; and raise their objections, if any. … (*Interruptions*) Madam, these amendments also have been moved and the Bill also has been introduced. … (*Interruptions*) The Minister is now talking on the Bill. … (*Interruptions*) Let it go on. … (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: This is not the way.

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Now, hon. Minister, Shri Arun Jaitley.

… (*Interruptions*)

SHRI ARUN JAITLEY: Madam, I beg to move:

> "That the Bill further to amend the Income-tax Act, 1961 and the Finance Act, 2016, be taken into consideration."

माननीय अध्यक्ष जी, 8 नवंबर 2016 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सामने एक महत्वपूर्ण घोषणा की थी। वह घोषणा थी कि 8 नवंबर की मध्य रात्रि से बड़े करेंसी नोट 500 या 1000 लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। ...(व्यवधान) इसके पीछे उद्देश्य यह था कि इस देश में जो काला धन है, जिसका प्रयोग टैक्स इवेज़न के लिए होता है, भ्रष्टाचार में प्रयोग होता है, उस सारे कालेधन को इस देश की राजनीति से, इस देश के आर्थिक जीवन से अलग किया जाए।...(व्यवधान) जिस दिन से यह सरकार बनी है, यह सरकार एक के बाद एक कालेधन के खिलाफ कदम उठाती रही है। 26 मई, 2014 को शपथ ली और 29 मई, 2014 को सरकार का पहला निर्णय था, साढ़े तीन साल से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया गया जो कालेधन को समाप्त करने के लिए अपनी रिकमेंडेशन दे। ...(व्यवधान) इसके पश्चात् विदेशों में जो काला धन था, उसके संबंध में सरकार ने कड़ी कार्रवाई की, ब्लैक मनी के बारे में कानून लाए, जिसके तहत 60 परसेंट टैक्स देने पर लोगों को अवसर दिया कि टैक्स वापस लाएं। कई लोग काला धन वापस लेकर आए।...(व्यवधान) इसके बाद एचएसबीसी और अन्य लिचेनस्टाइन के खातों में जो काला धन था, उस काले धन के संबंध में जिसके खिलाफ असेसमेंट करना था, जिसके खिलाफ मुकदमा चलाना था, सरकार ने चलाया। ...(व्यवधान) इसके पश्चात् बेनामी संपत्ति को सरकार जब्त कर ले और बेनामी संपत्तियां ट्रांसफर करने वाले लोगों को सजा हो, संसद के माध्यम से एक कानून पारित किया।...(व्यवधान)

सरकार की आईडीएस स्कीम इतिहास में सबसे सफल योजना थी, जिसमें लगभग 70,000 करोड़ रुपए के करीब काला धन उभर कर बाहर आया।...(व्यवधान) इसके बाद भी जब सरकार ने एक नया निर्णय कालेधन के संबंध में किया, 8 नवंबर के बाद यह देखने को मिला कि कई लोग वो करेंसी नोट, जो लीगल टेंडर नहीं थे, को गैर कानूनी तरीके से बदलने का प्रयास कर रहे थे।...(व्यवधान) बाजार की इन हरकतों को देखने के बाद सरकार अपनी योजना के तहत इनकम टैक्स कानून और फाइनेंस बिल में संशोधन लाई। इस संशोधन का आधार यह है कि जो लोग गैर कानूनी तरीके से इस कालेधन को बदलने के प्रयास में पकड़े जाएंगे, उनके ऊपर 60 परसेंट टैक्स और उसके साथ पैनल्टी के प्रावधान लगेंगे, कुल मिलाकर 85 परसेंट टैक्स और हर्जाना लागू होगा।...(व्यवधान) लेकिन कोई भी व्यक्ति अगर उस काले धन को बैंक में

जमा कराता है और उसे डिसक्लोज करता है तो 50 फीसदी टैक्स लगेगा, इस 50 फीसदी टैक्स में सरचार्ज भी होगा और पैनल्टी भी होगी। इसके अलावा 50 परसेंट बकाया में से 25 परसेंट वापस मिल जाएगा और 25 परसेंट चार साल बाद वापस मिलेगा। ...(व्यवधान) कुल मिलाकर प्रयास होगा कि यह पैसा मुख्यधारा में वापस आ जाए।

केन्द्र सरकार को इससे साधन मिलेंगे, जो आज तक काले धन में छुपे हुए थे। ...(व्यवधान) उन साधनों को गरीब कल्याण कोष के रूप में बनाया जायेगा और ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन करने के लिए उस सारे कोष को लगाया जायेगा। ...(व्यवधान) आज अमीरों के पास जो काला धन था, वह गरीब के हित में प्रयोग होगा, यह इस कानून का उद्देश्य है। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया, मैं इस सदन से गुजारिश करता हूं कि इस संशोधन को स्वीकार किया जाये। ...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: There will be no discussion.

… (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : जो भी प्वाइंट ऑफ आर्डर्स उठाये गये हैं, in view of the urgency involved, we have to dispose of the Bill today itself. कल बिल इंट्रोड्यूस हुआ था और आज यह पारित होने के लिए आ रहा है, अमेंडमैंट्स भी आ रहे हैं, इसलिए कोई प्वाइंट ऑफ आर्डर स्टैंड नहीं करता है।

दूसरी बात यह है कि जो अमेंडमैंट ऐसी आयी है, जिसमें प्रेजिडैंट की रिकमेंडेशन जरूरी है, but there is no time, so I cannot permit such amendments to be moved. Therefore, I cannot permit the Members moving of such amendments which require the President's recommendation. Now, we will take up the Bill.

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Hon. Members, the Taxation Laws (Second Amendment) Bill, 2016 is a Bill of vital public importance. It is my earnest desire that the House should have a thorough debate on this Bill. However, in the prevailing situation, it is not possible to have a discussion on this Bill. It is impossible because of the way all of you are behaving. It is impossible to have a discussion on this Bill. The Hon. Members will appreciate that this Bill is required to be considered and passed by this House. Therefore, I will put further motions in regard to the Bill directly to the vote of the House.

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: I am sorry to say that this is not the way.

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: You do not want a discussion, and I cannot help it. If you want a discussion, please go back to your seats, and I am ready for it.

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: The question is:

> "That the Bill further to amend the Income-tax Act, 1961 and the Finance Act, 2016, be taken into consideration."

The motion was adopted.

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: The House will now take up clause-by-clause consideration of the Bill.

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Hon. Members, Sarvashri N.K. Premachandran, B. Mahtab, Rajeev Satav and K.C. Venugopal have tabled amendments to the Taxation Laws (Second Amendment) Bill. I may inform the House that amendment Nos. 1,2,3, 6 and 7 by Shri N.K. Premachandran; amendment No. 11 by Shri B. Mahtab; both the amendments tabled by Shri Rajeev Satav, and amendment No. 12 by Shri K.C. Venugopal require recommendation of the President under clause (1) of Articles 117 and 274 of the Constitution for moving in Lok Sabha. Since the recommendation of the President for moving the amendments has yet not been received, hon. Members cannot be permitted to move these amendments. However, I will call Shri Mahtab and Shri N.K. Premachandran to move their amendments which do not require President's recommendation.

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: The question is:

> "That clauses 2 to 4 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clauses 2 to 4 were added to the Bill.

Clause 5 ***Amendment of Section 2***

HON. SPEAKER: Shri N.K. Premachandran, are you moving your amendment Nos. 4, 5, 8 and 9 to clause 5 of the Bill?

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): I am not moving.

HON. SPEAKER: He is not moving the amendments.

… (*Interruptions*)

15.00 hours

HON. SPEAKER: Shri Bhartruhari Mahtabji, are you moving your amendment no. 10?

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Madam, I beg to move:

"Page 4, lines 28 to 30,-

Omit "and shall also fulfil such other conditions as may be specified in the *Pradhan Mantri Garib Kalyan* Deposit Scheme, 2016.". (10)

The sentence can continue in the Part II. But the other part which I have mentioned should be omitted. … (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: I shall now put amendment No. 10 to clause 5 moved by Shri Bhartruhari Mahtab to the vote of the House.

The amendment was put and negatived.

The question is:

"That clause 5 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 5 was added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Long Title were added to the Bill.

HON. SPEAKER: The Minister may now move that the Bill be passed.

SHRI ARUN JAITLEY: I beg to move:

"That the Bill be passed."

HON. SPEAKER: The question is:

"That the Bill be passed."

The motion was adopted.

HON. SPEAKER: I am really sorry that you are not discussing the important Bill.

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: The House stands adjourned to meet tomorrow the 30th November, 2016 at 11.00 a.m.

15.02 hours

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday, November 30, 2016/Agrahayana 9, 1938 (Saka).